

लक्ष्मण नादर और अन्य

बनाम

आर. रैमियर.

{मेहर चंद महाजन और एस. आर. दास जे.जे.,}

हिंदू कानून-वसीयत-पत्नी को उसके जीवन भर के लिए और पत्नी के जीवनकाल के बाद बेटी को वसीयत करना-पत्नी द्वारा ली गई संपत्ति-चाहे सामान्य जीवन की संपत्ति हो या हिंदू विधवा की संपत्ति-बेटी की संपत्ति-चाहे निहित हो-विधवा से पहले बेटी की मृत्यु, इसका प्रभाव-निर्माण हिंदू इच्छा-निर्देशक सिद्धांत।

मिताक्षरा कानून द्वारा शासित एक हिंदू ब्राह्मण ने एक वसीयत बनाई जिसमें उन्होंने निम्नलिखित निर्देश दिए “मेरे जीवनकाल के बाद, आप, उपरोक्त रंगनायकी अम्मल, मेरी पत्नी, अपने जीवनकाल तक उपरोक्त संपूर्ण संपत्तियों का आनंद लेंगी... आपके बाद जीवनकाल, रामालक्ष्मी अम्मल, हमारी बेटी और उसके उत्तराधिकारियों को पीढ़ियों तक उपहार, विनिमय और बेटे से पोते को बिक्री आदि जैसे अलगाव के पूर्ण अधिकार और शक्तियों का आनंद मिलेगा। सी को किए जाने वाले भरण-पोषण के भुगतान के संबंध में मेरे दिवंगत बेटे एच की पत्नी, मेरी पत्नी रंगनायकी अम्मल अपनी इच्छानुसार भुगतान करेगी और रिहाई विलेख प्राप्त करेगी। वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी ने उसकी

संपत्तियों पर कब्ज़ा कर लिया, लेकिन उसकी पत्नी की मृत्यु से पहले, उसकी बेटी और उसके सभी बच्चे मर गए

माना गया, (1) कि आस-पास की परिस्थितियों के आलोक में वसीयत के उचित निर्माण पर, वसीयतकर्ता ने उसे सम्मानित किया था पत्नी केवल एक साधारण जीवन संपत्ति है, और उसके द्वारा किया गया परायापन अपने जीवनकाल के बाद सहन नहीं करेगी

(2) वसीयतकर्ता की बेटी को वसीयत के तहत प्राप्त किया गया विधवा के जीवनकाल के बाद संपत्तियों में निहित स्वार्थ, जिस पर उसका पति उसकी मृत्यु पर सफल हुआ। सादृश्य द्वारा निर्माण का नियम खतरनाक हैं। वसीयत को अलग-अलग शब्दों में परिभाषित करें और निष्पादित करें अलग-अलग परिवेश में।

राम बहादुर बनाम. जागर नाथ प्रसाद (3 पैट. एल.जे. 199)। पावनी सुब्बम्मा बनाम. अरुमाला राम नायडू (1937, 1 एम.एल.जे. 268), नाथू राम महाजन बनाम गंगा बाई (1988, 2 एम.एल.जे. 562), वसंत राव अम्मानम्मा बनाम वेंकट कोडंडा बाओ (1940, 1 एम.एल.जे. 188), कोल्हापुर के मालाराजा बनाम सुंदरम अय्यर (आई.एल.आर. 48 मद. 1), महोमेद शुसूल बनाम। शेवकराम (2 एल.ए. 7)। रत्ना चेट्टी बनाम नारायणस्वामी चेट्टी (26 एम.एल.जे. 616), एमएसटी भगवती देवी बनाम

चौधरी भोलोनाथ ठाकुर (2 1.ए. 256) एवं लल्लू बनाम. जगमोहन (आई एल आर 22 बोम 409) का उल्लेख किया गया है।

मद्रास हाई कोर्ट के फैसले की पुष्टि. निर्णय:

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 95/1952

की अपील संख्या 635 में मद्रास उच्च न्यायालय (राव और अय्यर जेजे) के 27 फरवरी, 1950 के फैसले और डिक्री के खिलाफ अपील। 1945 के मूल वाद संख्या 50 में टिनेवेल्ली के अधीनस्थ न्यायाधीश की अदालत का 13 अगस्त, 1946 का निर्णय और डिक्री की।

के.एस.कृष्णास्वामी अयंगर (एस.रामचंद्र अय्यर, उसके साथ) अपीलकर्ताओं के लिए।

प्रतिवादी की ओर से के. राजा अय्यर (आर. गणपति अय्यर, उनके साथ)।

14 अप्रैल 1953 न्यायालय का निर्णय सुनाया गया -

महाजन जे.-वन लक्ष्मीनारायण अय्यर, एक हिंदू ब्राह्मण, जिनके पास तिरुनेलवेली जिले में काफी संपत्ति थी, की 13 दिसंबर, 1924 को मृत्यु हो गई, जिससे उनकी विधवा रंगनायकी और एक विवाहित बेटी रामालक्ष्मी जीवित रहीं। रामालक्ष्मी ने वादी से शादी की थी और उससे उनके कई बच्चे थे। दिसंबर, 1924 में जब लक्ष्मीनारायण की मृत्यु हुई, तब वे सभी जीवित थे। अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने 16 नवंबर, 1924 को

एक वसीयत निष्पादित की गई, जिसका निर्माण इस अपील में विवाद में है। इस वसीयत के द्वारा उन्होंने निम्नलिखित निर्देश दिये

"मेरे जीवनकाल के बाद, आप, उपरोक्त रंगनायकी अम्मल, मेरी पत्नी, अपने जीवनकाल तक उपरोक्त संपूर्ण संपत्तियों, मेरे कारण बकाया, मेरे द्वारा देय ऋण और मेरे द्वारा देय चिट राशि का आनंद लेंगे। आपके जीवनकाल के बाद रामालक्ष्मी अम्माल, हमारी बेटी और मेलागरम गांव के राम अय्यर एवर गैल की पत्नी, और उसके उत्तराधिकारियों को पीढ़ियों तक उपहार, विनिमय और बेटे से पोते को बिक्री जैसे अलगाव के पूर्ण अधिकार और शक्तियां मिलेंगी। जहां तक भुगतान का संबंध है मेरे दिवंगत बेटे हरिहरमय्यान की पत्नी चिन्नानिमल उर्फ लक्ष्मी अम्मल को भरण-पोषण का भुगतान किया जाएगा, मेरी पत्नी रंगनायकी अम्मल अपनी इच्छानुसार इसका भुगतान करेगी और रिहाई विलेख प्राप्त करेगी।"

रंगनायकी ने अपने पति की मृत्यु के बाद संपत्तियों पर कब्जा कर लिया। 21 फरवरी, 1928 को, उन्होंने लक्ष्मी अम्मल के भरण-पोषण के दावे का निपटारा किया और उन्हें रुपये का भुगतान करके उनसे रिहाई का एक दस्तावेज प्राप्त किया। 3,350 नकद और उसके पक्ष में एक समझौता निष्पादित करके उसे रुपये का भुगतान करने का प्रावधान किया गया। 240 प्रति वर्ष.

विधवा के जीवनकाल में ही 25 अप्रैल, 1938 को रामलक्ष्मी की मृत्यु हो गई। उसका कोई भी बच्चा जीवित नहीं बचा। 24 जुलाई, 1945 को, विधवा ने खुद को अपने पति की संपत्तियों का पूर्ण मालिक बताते हुए संपत्ति की एक वस्तु दूसरे प्रतिवादी को रुपये में बेच दी। 500. 18 सितंबर, 1945 को, जिस मुकदमे से यह अपील उत्पन्न हुई, वह वादी, पति और रामलक्ष्मी के एकमात्र उत्तराधिकारी द्वारा एक घोषणा के लिए दायर किया गया था कि उक्त बिक्री जीवन भर के लिए उस पर बाध्यकारी नहीं होगी। विधवा का प्रार्थना की गई कि विधवा को उसके कब्जे की अन्य संपत्तियों को हस्तांतरित करने से रोका जाए। 19 सितंबर, 1945 को, उच्च न्यायालय द्वारा एक अंतरिम निषेधाज्ञा जारी की गई थी, जिसमें विधवा को अपने कब्जे वाली संपत्तियों को अलग करने और अपने पति की संपत्ति का हिस्सा बनने से रोक दिया गया था। इस निषेधाज्ञा के बावजूद, 27 सितंबर, 1945 को, उन्होंने अन्य प्रतिवादियों के पक्ष में निपटान के दो कार्य निष्पादित किए, जिनमें कई संपत्तियाँ भी शामिल थीं। वादी को अपनी याचिका में संशोधन करने और उसमें इन अलगावों की अमान्यता के संबंध में एक घोषणा के लिए प्रार्थना भी शामिल करने की अनुमति दी गई थी। वादपत्र में यह दावा किया गया था कि रामलक्ष्मी ने अपने पिता की वसीयत के तहत मुकदमे की संपत्तियों में शेष हित प्राप्त किया था और इस प्रकार वादी मुकदमे को बनाए रखने का हकदार था।

प्रतिवादियों ने दलील दी कि वादी के पास मुकदमे को कायम रखने का कोई अधिकार नहीं था, कि विधवा वसीयत के तहत पूर्ण संपत्ति की हकदार थी या कम से कम एक विधवा की संपत्ति के अनुरूप और उससे कम संपत्ति की हकदार नहीं थी, कि संपत्ति रामालक्ष्मी को दी गई थी वसीयत केवल एक आकस्मिक थी और विधवा की पहले ही मृत्यु हो जाने के कारण, वादी को हस्तांतरित मुकदमे की संपत्तियों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुकदमे में मुख्य मुद्दा यह था कि क्या विधवा ने वसीयत के तहत पूर्ण संपत्ति ली थी या हिंदू विधवा की संपत्ति जैसी संपत्ति ली थी और क्या उसमें बेटी का हित आकस्मिक शेष की प्रकृति में था, या क्या उसे संपत्ति निहित अधिकार मिला था।

अधीनस्थ न्यायाधीश ने माना कि विधवा ने वसीयत के तहत सीमित जीवन हित लिया, न कि पूर्ण संपत्ति या यहां तक कि हिंदू कानून के तहत विधवा की संपत्ति भी नहीं, और इसके तहत बेटी को उन संपत्तियों में निहित स्वार्थ मिला, जिन पर वादी का उत्तराधिकार था। उसकी मौत। इस निष्कर्ष को ध्यान में रखते हुए उन्होंने वादी को इस आशय का एक घोषणात्मक डिक्री प्रदान किया कि पहले प्रतिवादी के पास केवल वाद संपत्ति में जीवन भर के लिए एक संपत्ति थी और उसके द्वारा किया गया अलगाव उसके जीवनकाल से अधिक नहीं रहेगा। अलगाव की वैधता का प्रश्न अनिर्णीत छोड़ दिया गया था। असफल प्रतिवादियों ने इस डिक्री के खिलाफ मद्रास उच्च न्यायालय में अपील दायर की। अपील के लंबित रहने

के दौरान 14 फरवरी, 1948 को विधवा की मृत्यु हो गई। उच्च न्यायालय ने अपील के तहत अपने फैसले से ट्रायल जज के फैसले की पुष्टि की और वसीयत के निर्माण पर अपना दृष्टिकोण बरकरार रखा। उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति दी गई 27 नवंबर, 1951 को अपील स्वीकार कर ली गई।

अपील में निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या वसीयतकर्ता द्वारा उसकी विधवा को दी गई संपत्ति हिंदू कानून के तहत एक पूर्ण महिला की संपत्ति थी या महाजन जे अभिव्यक्ति के अंग्रेजी अर्थ में केवल एक सीमित जीवन संपत्ति थी। हमारे सामने इस बात का विरोध नहीं किया गया है कि एक हिंदू एक सीमित अवधि के लिए जीवन संपत्ति, या क्रमिक जीवन संपत्ति, या कोई अन्य संपत्ति बना सकता है, बशर्ते कि दान या इसके तहत लेने वाले व्यक्ति एक विलेख के तहत लेने में सक्षम हों। या होगा। अपील का निर्णय इस प्रकार इस प्रश्न पर केंद्रित है कि क्या वसीयतकर्ता का इरादा अपनी विधवा को एक साधारण जीवन संपत्ति या एक हिंदू विधवा के समान संपत्ति देने का था। एक समय यह विवादास्पद मुद्दा था कि क्या एक हिंदू विधवा की संपत्ति वसीयत द्वारा बनाई जा सकती है, यह कानून द्वारा बनाई गई संपत्ति है, लेकिन अब यह तय हो गया है कि एक हिंदू अपनी विधवा को वसीयत के माध्यम से वही संपत्ति प्रदान कर सकता है जो वह करती है। विरासत से मिलेगा। ऐसे मामले में विधवा को मृतक के रूप में लिया जाता है न कि उत्तराधिकारी के रूप में।

ऐसे मामलों में अदालत का प्राथमिक कर्तव्य आसपास की परिस्थितियों, उसकी संपत्ति के हस्तांतरण, उसके पारिवारिक रिश्तों के संबंध में एक हिंदू के रूप में उसकी सामान्य धारणाओं को ध्यान में रखते हुए, वसीयतकर्ता द्वारा प्रयुक्त भाषा से यह पता लगाना है कि उसके इरादे क्या थे। वगैरह।; दूसरे शब्दों में, स्वयं को उसकी आरामकुर्सी पर रखकर उसकी इच्छाओं का पता लगाना। इन सिद्धांतों के आलोक में वसीयत पर विचार करने पर, हमें ऐसा लगता है कि लक्ष्मीनारायण अय्यर ने अपनी वसीयत से यह निर्देश देने का इरादा किया था कि उनकी संपूर्ण संपत्ति का उपयोग उनकी विधवा को अपने जीवनकाल के दौरान करना चाहिए, लेकिन उन संपत्तियों में उनकी रुचि उनकी मृत्यु पर समाप्त हो जानी चाहिए। , कि इन सभी संपत्तियों को पूरी तरह से उसके बाद उसकी बेटी और उसके उत्तराधिकारियों द्वारा पीढ़ी-दर-पीढ़ी अलगाव, उपहार, विनिमय और बिक्री की शक्तियों के साथ पूर्ण मालिकों के रूप में आनंद लिया जाना चाहिए। वह अपनी बेटी को नया वंश बनाना चाहता था ताकि उसकी संतान, पुरुष या महिला, को उसकी संपत्ति का लाभ मिल सके। वे वास्तविक व्यक्ति थे जिन्हें उन्होंने निश्चितता के साथ अंतिम प्राप्तकर्ता के रूप में चिन्हित किया था

उसका इनाम. स्पष्ट शब्दों में उन्होंने अपनी बेटी को उपहार, विनिमय, बिक्री के माध्यम से अलगाव की शक्तियाँ प्रदान कीं, लेकिन इसके ठीक विपरीत, उन्होंने अपनी विधवा को ऐसी कोई शक्तियाँ प्रदान

नहीं कीं। उसके लिए निर्देश यह था कि उसे बकाया आदि सहित संपूर्ण संपत्तियों का आनंद लेना चाहिए और उसके बाद ये उसकी बेटियों को दे दी जाएंगी। हालाँकि आवश्यकता पड़ने पर उसकी अलगाव की शक्तियों पर व्यक्त शब्दों में कोई रोक नहीं लगाई गई थी, यहाँ तक कि उसे व्यक्त शब्दों में वह सीमित शक्ति भी नहीं दी गई थी। यदि वसीयतकर्ता के मन की आंखों के सामने उसकी बेटी और उसके उत्तराधिकारी उसके इनाम के अंतिम लाभार्थी हैं, तो यह इरादा केवल विधवा को एक सीमित संपत्ति देकर ही प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि एक पूर्ण हिंदू विधवा की संपत्ति को उसकी बेटी को प्रदान करने से ही प्राप्त किया जा सकता है। वसीयत, हिंदू कानून के तहत केवल एक विशेष उत्तराधिकार है जो परिपक्व हो भी सकती है और नहीं भी और वसीयत के तहत उसका हित केवल उस चीज़ में आकस्मिक होगा जो विधवा द्वारा अप्राप्य छोड़ दिया गया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि वसीयतकर्ता ने वसीयत में यह नहीं कहा कि बेटी केवल विधवा द्वारा छोड़ी गई संपत्ति का ही उपभोग करेगी। जहां तक अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों का संबंध है, बेटी और विधवा को अनुदान की सीमा समान है। जिस प्रकार विधवा को अपने जीवनकाल के दौरान अनुसूची में उल्लिखित संपूर्ण संपत्तियों का आनंद लेने के लिए निर्देशित किया गया था, उसी प्रकार बेटी और उसके उत्तराधिकारियों को भी पीढ़ी-दर-पीढ़ी पूर्ण अधिकारों के साथ समान संपत्तियों का आनंद लेने के लिए निर्देशित किया गया था। यदि विधवा के पास पूरी तरह से हिंदू विधवा की संपत्ति है और

किसी भी उद्देश्य के लिए उनका निपटान करने की शक्ति है और ऐसा किया जाता है, तो वे निर्देशित तरीके से समान संपत्तियों का आनंद नहीं ले सकते हैं। यदि यही इरादा होता तो वसीयतकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा होता कि बेटी केवल विधवा की मृत्यु के बाद बची हुई संपत्ति ही लेगी। यह नहीं माना जा सकता कि विधवा को वसीयत के तहत पूर्ण हिंदू विधवा की संपत्ति दी गई है, जब तक कि यह नहीं कहा जा सकता कि इसकी शर्तों के तहत उसे आवश्यक उद्देश्यों के लिए अलगाव की शक्ति दी गई थी, चाहे स्पष्ट शब्दों में या आवश्यक निहितार्थ द्वारा। जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्पष्ट रूप से स्पष्ट शब्दों में अलगाव की शक्ति उसे प्रदान नहीं की गई थी। यह तर्क दिया गया कि ऐसी शक्ति उन कृत्यों के भीतर निहित थी जिन्हें करने के लिए वह अधिकृत थी, यानी, जब उसे ऋणों का भुगतान करने और रामलक्ष्मी के भरण-पोषण का निपटान करने के लिए निर्देशित किया गया था, तो इन निर्देशों के भीतर यह निहित था कि इन उद्देश्यों के लिए, यदि आवश्यकता हुई, वह संपत्तियों को अलग कर सकती है। इस वसीयत के निष्पादन में शामिल आसपास की परिस्थितियों में इस सुझाव को बरकरार नहीं रखा जा सकता है। वसीयत द्वारा निपटाई गई और अनुसूची में उल्लिखित संपत्तियों की मात्रा काफी थी और ऐसा लगता है कि उनसे विधवा को वसीयत के तहत दायित्वों को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आय प्राप्त हुई। वास्तव में हमने पाया कि वसीयतकर्ता की मृत्यु के चार साल के भीतर विधवा रुपये की एकमुश्त

राशि का भुगतान करने में सक्षम थी। अचल संपत्तियों का कोई भी हिस्सा दिए बिना बहू को 3,350 रुपये नकद दिए और संभवतः इस समय तक उसने सभी ऋणों का भुगतान कर दिया था। यह नहीं दिखाया गया है कि उन्होंने अपने पति की मृत्यु के बाद 21 वर्ष से अधिक की अवधि में, वर्ष 1945 तक अचल संपत्ति की एक भी वस्तु को अलग कर दिया था, एक को छोड़कर, जिसे उन्होंने वर्ष 1937 में रुपये की राशि जुटाने के लिए अलग कर दिया था। कुछ जमीन खरीदने के लिए 1,000 रु. इस लेन-देन के द्वारा उसने एक संपत्ति के स्थान पर दूसरी संपत्ति रख ली। अपने भरण-पोषण के उद्देश्य से, ऋण आदि के भुगतान के लिए, और बहू के दावे का निपटारा करने के लिए उसे अनुसूची में उल्लिखित संपत्ति के किसी भी हिस्से का कोई भी हस्तांतरण करने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं हुई है और वसीयतकर्ता को पूरी संभावना थी कि वह अलगाव का सहारा लिए बिना इन दायित्वों को पूरा कर सकती है और इसलिए उसने उसे ऐसा करने की कोई शक्ति नहीं दी। इस स्थिति में यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता है कि वसीयतकर्ता के पास उन सीमित उद्देश्यों के लिए विधवा को अलगाव की शक्ति प्रदान करने का इरादा होना चाहिए। हमारी राय में, भले ही उस सुझाव को स्वीकार कर लिया जाए कि वसीयत में उल्लिखित सीमित उद्देश्यों के लिए विधवा अलग हो सकती है, यह शक्ति उन शक्तियों से बहुत कम होगी जो एक हिंदू विधवा को हिंदू कानून के तहत प्राप्त हैं। उस कानून के तहत उसे पति की आत्मा के लाभ के लिए,

तीर्थयात्रा के लिए और संपत्ति के लाभ के लिए संपत्ति को अलग करने की शक्ति है, अन्य अधिकृत उद्देश्य. यह नहीं कहा जा सकता है कि एक हिंदू विधवा अपने पति की संपत्ति को केवल ऋणों के भुगतान, रखरखाव शुल्क को पूरा करने और अपने स्वयं के रखरखाव के लिए अलग कर सकती है। वह सभी प्रकार से संपत्ति का प्रतिनिधित्व करती है और उसे बहुत व्यापक शक्ति प्राप्त है, सिवाय इसके कि वह आवश्यकता के अलावा इसे अलग नहीं कर सकती है और उसकी आवश्यकताओं को विभिन्न प्रकार के महाजन जे विचारों पर आंका जाना चाहिए। इसलिए हमारा मानना है कि रंगनायकी अम्मल को प्रदान की गई संपत्ति उपरोक्त निर्देशों के बावजूद एक पूर्ण हिंदू विधवा की संपत्ति की तुलना में अंग्रेजी अर्थ में सीमित संपत्ति की तरह थी। अपने जीवनकाल के दौरान संपत्ति की आय पर उसका पूरा नियंत्रण था लेकिन उसके पास संपत्ति के कोष से निपटने की कोई शक्ति नहीं थी और इसे बेटी के आनंद के लिए बरकरार रखना पड़ता था। हालाँकि बेटी संपत्ति पर तत्काल कब्ज़ा पाने की हकदार नहीं थी, लेकिन निश्चितता के साथ संकेत दिया गया था कि उसे उचित समय पर पूरी संपत्ति मिलनी चाहिए और इस प्रकार वसीयतकर्ता की मृत्यु पर उसे इसमें ब्याज मिल गया। उसे संपत्ति में भविष्य के आनंद का वर्तमान अधिकार दिया गया था। जरमन के अनुसार (जर्मन ऑन विल्स), कानून सम्पदा को निहित करने के पक्ष में है और वसीयत प्रभावी होने पर निपटान की गई संपत्ति उपहार की वस्तु से संबंधित होती है और हमें लगता है कि इस वसीयत के तहत

बेटी को वसीयतकर्ता की संपत्तियों में निहित स्वार्थ मिला है। उनकी मृत्यु पर संपत्ति।

श्री के.एस. कृष्णस्वामी अयंगर द्वारा दृढ़तापूर्वक यह तर्क दिया गया था कि लक्ष्मीनारायण अय्यर एक ब्राह्मण सज्जन थे जो संभवतः शास्त्रों में पारंगत थे, जो मद्रास राज्य के सबसे दक्षिणी भाग में एक गाँव में रहते थे, कि प्रतिबंधित संपत्ति का उनका विचार एक समान होने की अधिक संभावना थी एक हिंदू महिला की संपत्ति को जीवन संपत्ति की तुलना में अंग्रेजी कानून में समझा जाता है, जिसमें संपत्ति को उपयोग से मापा जाता है, न कि अवधि से, और यदि इस वसीयत को लक्ष्मीनारायण लेयर की धारणाओं के प्रकाश में समझा जाता है, तो यह माना जाना चाहिए कि विधवा को मिला इसके तहत एक हिंदू विधवा की संपत्ति थी और बेटी को विशेष प्रकृति में आकस्मिक शेष मिलता था और उसकी मृत्यु पर वादी को कुछ भी हस्तांतरित नहीं किया जा सकता था और इस प्रकार उसके पास विधवा द्वारा किए गए अलगाव पर सवाल उठाने का कोई अधिकार नहीं था। विद्वान वकील ने अपने तर्क के समर्थन में हमारा ध्यान विभिन्न उच्च न्यायालयों के कई निर्णयों की ओर आकर्षित किया और तर्क दिया कि इस वसीयत के शब्दों को उसी तरह से समझा जाना चाहिए जैसे कि कमोबेश इसी तरह के शब्दों का अर्थ वसीयत में अदालतों द्वारा लगाया गया था। उन निर्णयों में. सादृश्य द्वारा निर्माण का यह नियम अलग-अलग परिवेश में अलग-अलग शब्दों में और निष्पादित की गई वसीयत का

अर्थ निकालने में खतरनाक है। ख्वीडियो ससीमन बनाम शिब नारायण,। हालाँकि, दोनों पक्षों के विद्वान वकीलों के सम्मान में, जिन्होंने दृष्टिकोण की समान पद्धति अपनाई, हम उनके द्वारा संदर्भित कुछ महत्वपूर्ण मामलों की जांच करने के लिए आगे बढ़ते हैं।

श्री कृष्णास्वामी अयंगर ने अपने विवाद के लिए सबसे बड़ा समर्थन राम बहादुर बनाम जगर नाथ प्रसाद () के फैसले से प्राप्त करने की कोशिश की। वसीयत में कहा गया है कि यदि वसीयतकर्ता के जीवनकाल में उसकी बेटी या बेटा पैदा होता है, तो ऐसा बेटा या बेटी उसकी सभी संपत्तियों का मालिक होगा, लेकिन अगर कोई बेटा या बेटी नहीं है, तो उसकी भतीजी एस को वसीयत मिलेगी। लाखों रुपए और बाकी चल-अचल संपत्ति उसकी पत्नी की मृत्यु तक उसके कब्जे में रहेगी और उसके बाद ये उसकी भतीजी के कब्जे में रहेगी। शेष का निपटान निम्नलिखित शब्दों में किया गया-

"यदि मेरी पत्नी और मेरी भतीजी की मृत्यु के बाद मेरे उक्त भाई की बेटी के गर्भ से जन्मे एक बेटा और एक बेटी जीवित हैं, तो चल संपत्ति का दो-तिहाई हिस्सा बेटे का होगा और एक तिहाई हिस्सा मेरा होगा। बेटी। लेकिन अचल संपत्ति के संबंध में किसी को भी अलगाव का

अधिकार नहीं होगा। वे निश्चित रूप से किराए के भुगतान के बाद शेष शेष का आनंद लेने के हकदार होंगे।"

इस वसीयत को भतीजी के बेटे और बेटी को पूर्ण संपत्ति देने के रूप में समझा गया था। यह टिप्पणी की गई थी कि अलगाव के खिलाफ एक स्पष्ट प्रतिबंध के बावजूद, एस (भतीजी) द्वारा ली गई संपत्ति एक ऐसी संपत्ति थी जिसे एक महिला आमतौर पर हिंदू कानून के तहत विरासत में प्राप्त करती है जिसे वह पूरी तरह से प्रतिनिधि चरित्र में रखती है लेकिन 491 असमर्थ है। कानूनी आवश्यकता के मामले को छोड़कर अन्यत्र अलग किया जा सकता है और ऐसा निर्माण सामान्य धारणाओं के अनुरूप था जो एक हिंदू की अपनी संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में होती है। इसमें शामिल प्रावधानों का उन प्रावधानों से कोई सादृश्य नहीं होगा जिनकी हमें व्याख्या करनी है। अलगाव के विरुद्ध प्रतिबंध जीवन संपत्ति और विधवा संपत्ति दोनों के प्रतिकूल था और इसलिए, इसे ध्यान में नहीं रखा गया था। लेकिन उस वसीयत में अन्य संकेत थे जो दर्शाते थे कि एक विधवा की संपत्ति दी गई थी। यह तथ्य कि उपहार एक आकस्मिक वसीयत थी, अपने आप में एक निश्चित संकेत के रूप में ली गई थी कि पिछली वसीयत एक विधवा की संपत्ति थी।

हमारे सामने वसीयत में ऐसा कोई संकेत नहीं है. अगला भरोसा पावनी सुब्बुम्मु बनाम अम्माला राम नायडू के फैसले पर रखा गया।

वसीयत के तहत, विधवा एस को संपत्तियों का आनंद लेना था और उसके जीवनकाल के बाद संपत्तियों को क्रमशः बेटे की बेटी और बेटी के बेटे द्वारा तीन से पांच के अनुपात में लिया जाना था। संपत्ति के एक मद में अपने हिस्से पर कब्जा पाने के लिए बेटे की बेटी द्वारा एक मुकदमा दायर किया गया था। संपत्ति का वह हिस्सा जो एस द्वारा बेचा गया था। उस मामले में निर्णय का प्रश्न यह था कि क्या एस. संपत्ति पर बाध्यकारी आवश्यकता को पूरा करने के प्रयोजनों के लिए भी अपने जीवन के हित से अधिक कुछ भी बेचने की हकदार थी। वरदाचारी जे. का मानना था कि चूँकि वसीयत में पोते-पोतियों को दिया गया उपहार पूरी संपत्ति का था, और मात्र पराजय के रूप में दिया गया उपहार नहीं था, इसलिए यह माना जाना चाहिए कि इससे संकेत मिलता है कि पूर्व उपहार विधवा के पक्ष में था केवल सीमित रुचि का था। इसलिए यह निर्णय विद्वान वकील के तर्क के विरुद्ध जाता है, लेकिन उन्होंने फैसले में की गई टिप्पणियों पर भरोसा किया जब विद्वान न्यायाधीश ने कहा, कोल्हापुर के महाराजा बनाम सुंदरम अय्यर में लिए गए दृष्टिकोण के सम्मान में, उपहार जोड़ने के बावजूद हिंदू कानून में एक महिला की संपत्ति के अनुरूप ब्याज पैदा करना संभव हो सकता है और एस द्वारा ली गई संपत्ति जरूरी नहीं कि अंग्रेजी कानून में केवल जीवन संपत्ति हो। शब्द का अर्थ है अवलोकन पारित करना वर्तमान मामले का निर्णय लेने में कैसे सहायक हो सकता है। यह मानते हुए कि उपहार जोड़ने के बावजूद एक हिंदू महिला की संपत्ति बनाना संभव है, फिर भी यह

सवाल कि क्या किसी दिए गए मामले में ऐसा किया गया था, विचाराधीन विशेष साधन की शर्तों पर निर्भर होना चाहिए।

नाथू राम महाजन बनाम गंगाबाई में प्रिवी काउंसिल के फैसले में निम्नलिखित टिप्पणियाँ थीं-

चूंकि वसीयत ने उसे अपने जीवनकाल के दौरान संपत्ति की आय का आनंद लेने का अधिकार दिया था, इसलिए यह स्पष्ट रूप से माना गया था कि विधवा के मामले में हिंदू कानून द्वारा प्रदान किए गए अनुसार, उसे संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। संपत्ति। पूरी तरह से अलग शर्तों में लिखी गई वसीयत के संबंध में की गई ऐसी आकस्मिक टिप्पणी मामले के निर्णय में बहुत मदद नहीं कर सकती है।

वसंतराव अम्मानम्मा बनाम वेंकट कोदंडा राव पंतुलु (2), अगले मामले का हवाला दिया गया, एक हिंदू वसीयतकर्ता जो उनके द्वारा प्रदान किया गया एक सेवानिवृत्त अधीनस्थ न्यायाधीश था उसकी वसीयत इस प्रकार थी-

"पूर्वाेक्त पैतृक भूमि में से, नौवां हिस्सा, जिसका मैं हकदार हूं, मेरी मृत्यु के बाद मेरी पत्नी को उसकी मृत्यु तक मिलेगा, और उसकी मृत्यु के बाद यह मेरे दूसरे बड़े भाई मृतक के बेटे एस को मिलेगा। मेरा मेरी मृत्यु के बाद स्व-अर्जित संपत्तियों का उपयोग मेरी पत्नी अपनी मृत्यु तक

करेगी और उसकी मृत्यु के बाद वे मेरी बेटी के पास चली जाएंगी। इसके बाद वे मेरी बेटी के माध्यम से मेरे पोते के पास चली जाएंगी।"

वसीयत को स्व-अर्जित संपत्तियों को अंततः पोते-पोतियों को देने के रूप में समझा गया था, और बेटी की संपत्ति की तुलना एक संपत्ति से की गई थी जिसे वह विरासत के कानून के तहत लेगी, जो कि एक विधवा की संपत्ति के अनुरूप एक सीमित संपत्ति है। रिपोर्ट के पृष्ठ 193 पर यह इस प्रकार देखा गया-

इसलिए सवाल उठता है कि क्या उनका इरादा केवल जीवन संपत्ति या बेटी की संपत्ति देने का था? ऐसा लगता है हमारे लिए उनका अभिप्राय जीवन संपत्ति के बजाय बेटी की संपत्ति देने से था। वह बेटी के पक्ष में स्वभाव के संदर्भ में श्उसके जीवन के दौरान श् शब्दों को छोड़ देता है। श्मेरी बेटी को हस्तांतरित श् शब्द यह संकेत देंगे कि हस्तांतरण की सामान्य प्रक्रिया में संपत्ति उसके पास चली जानी चाहिए, यानी बेटी के पास और फिर पोते-पोतियों के पास। भव्य के पक्ष में इस्तेमाल किये गये शब्द. बेटे संकेत करते प्रतीत होते हैं कि बेटी को दी गई संपत्ति जीवन भर की संपत्ति नहीं थी क्योंकि पोते के पक्ष में कोई प्रत्यक्ष उपहार नहीं है, लेकिन दूसरी ओर, वह जो कहते हैं वह यह है कि उनकी बेटी के माध्यम से संपत्ति उनके पोते को मिलेगी। या तो उसका इरादा यह रहा होगा कि

बेटी संपत्ति को वसीयत द्वारा या अंतरविरोध से पोते-पोतियों को हस्तांतरित कर दे या उसने संपत्ति ले ली है, उसके माध्यम से यह हस्तांतरण के सामान्य तरीके से पोते-पोतियों को मिल जानी चाहिए। यदि यह बेटी की संपत्ति थी जिसे प्रदान करने का इरादा था, तो इसमें कोई सवाल नहीं हो सकता है कि पोते द्वारा ली गई संपत्ति निहित स्वार्थ नहीं है।¹³ विद्वान न्यायाधीशों को अपील करने वाली तर्क की यह पंक्ति यहां हमारे लिए ज्यादा मददगार नहीं है क्योंकि इस वसीयत में भाषा बिल्कुल अलग है। यदि तर्क की वही पंक्ति यहां अपनाई जाती है, तो मामले का निर्णय श्री के.एस.के. अयंगर के मुवक्किल के खिलाफ जाएगा क्योंकि इस मामले में वसीयत में विधवा की संपत्ति को शब्दों द्वारा सीमांकित किया गया है। आपके जीवनकाल तक।

अगला भरोसा कोल्हापुर के महाराजा बनाम सुंदरम अय्यर (श) पर रखा गया। यह उसमें निर्धारित विशेष शर्तों पर सरकारी अनुदान का मामला था और अनुदान की प्रकृति पर सवाल उठा। वहां यह कहा गया था कि शिवाजी राजा की विधवाओं को एक हिंदू विधवा की सामान्य संपत्ति के समान जीवन संपत्ति का उपहार मिला और एक विधवा की संपत्ति से वंचित होने के दायित्व को छोड़कर, लेकिन फिर भी एक जीवन संपत्ति का उपहार मिला विरासत की संपत्ति की तुलना में।¹⁴ ये टिप्पणियाँ हमारे सामने मौजूद मुद्दे पर अधिक प्रकाश नहीं डालतीं।

अंतिम उल्लेखित निर्णय महोमेद शमसूल बनाम शेवुक्रम में प्रिवी काउंसिल का निर्णय था। वहां के एक दस्तावेज़ द्वारा बिहार के एक हिंदू निवासी एक वसीयतनामा पात्र ने अपनी बेटी को, जिसकी दो बेटियाँ थीं, अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, और उसके बाद, उसकी दो बेटियों को उनके बच्चों के साथ घोषित किया गया। वारिस और मलिक. पुत्री की एक पुत्री पूर्वा. वसीयतकर्ता को बिना किसी समस्या के समाप्त कर दिया गया और दूसरी बेटी- आर. रेमियर टेर की वसीयतकर्ता की मृत्यु के बाद मृत्यु हो गई, जिससे उसका एकमात्र बेटा, उस मामले में प्रतिवादी, रह गया। प्रतिवादी द्वारा अपनी दादी (वसीयतकर्ता की बेटी) के खिलाफ एक मुकदमे में, उक्त भूमि पर अपने भविष्य के अधिकार और शीर्षक को बरकरार रखने के लिए एक घोषणात्मक आदेश के लिए, यह माना गया कि बेटी ने अपनी बेटियों के अधीन एक संपत्ति ले ली है। इस निर्णय में निम्नलिखित टिप्पणियों को इस जांच के लिए प्रासंगिक मानते हुए जोर दिया गया -

यह तर्क दिया गया है कि ये बाद की अभिव्यक्तियाँ पूर्व अभिव्यक्तियों की व्यापकता को योग्य बनाती हैं, और वसीयत को समग्र रूप से लेते हुए, वसीयतकर्ता के इरादे को सूचित करने के रूप में समझा जाना चाहिए कि एमएसटी। रानी धुन कौर को पूर्ण संपत्ति नहीं लेनी चाहिए, बल्कि उनकी दो बेटियों को उनकी संपत्ति में उत्तराधिकारी बनाया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, उसे एक हिंदू विधवा की सामान्य संपत्ति की तरह ही संपत्ति लेनी चाहिए। किसी हिंदू की इच्छा का अर्थ लगाते समय

संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में हिंदुओं की सामान्य धारणाओं और इच्छाओं को ध्यान में रखना अनुचित नहीं है। यह माना जा सकता है कि एक हिंदू आम तौर पर चाहता है कि एक संपत्ति, विशेष रूप से पैतृक संपत्ति, उसके परिवार में बनी रहे; और यह माना जा सकता है कि एक हिंदू जानता है कि, एक सामान्य नियम के रूप में, सभी घटनाओं में, महिलाएं विरासत की पूर्ण संपत्ति नहीं लेती हैं, जिसे वे अलग करने में सक्षम हैं। ये टिप्पणियाँ अपरिहार्य हैं, लेकिन यह भी बताया जा सकता है कि एक हिंदू के लिए यह खुला है कि वह अपनी विधवा को एक सीमित जीवन संपत्ति या एक विधवा द्वारा उत्तराधिकारी के रूप में ली जाने वाली संपत्ति से भी बड़ी संपत्ति प्रदान कर सकता है और हर मामले में वह यह संपत्ति प्रदान नहीं कर सकता है। उसे वसीयत करके एक हिंदू विधवा की संपत्ति मिलेगी जो उसे अन्यथा विरासत में मिलती। आम तौर पर कहें तो, वसीयत बनाने का कोई मतलब नहीं होगा यदि विधवा को जो दिया जाना है वह उसे बिना वसीयत के प्राप्त होगा और ऐसे मामले सामने आते हैं जहां एक हिंदू अपनी विधवा को निर्वसीयता पर मिलने वाली संपत्ति से अधिक प्रतिबंधित संपत्ति या उससे कहीं अधिक बड़ी संपत्ति देना चाहता है। प्रत्येक मामले में प्रश्न केवल इस सिद्धांत पर निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि प्रत्येक हिंदू केवल एक हिंदू विधवा की संपत्ति के बारे में सोचता है और इससे अधिक के बारे में नहीं। जो दिया जाता है उसे आस-

पास की परिस्थितियों के आलोक में वसीयत की भाषा से इकट्ठा किया जाना चाहिए।

प्रतिवादी के विद्वान वकील ने श्री कृष्णास्वामी अयंगर द्वारा अपनाई गई लाइन का पालन किया। वह अन्य वसीयतों और उनकी शर्तों पर दिए गए निर्णयों की तर्ज पर इस वसीयत के निर्माण पर भी अपने पक्ष में निर्णय चाहता था। पहले उदाहरण में, उन्होंने रत्ना चेट्टी बनाम नारायणस्वामी चेट्टी मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले पर भरोसा जताया। वहां वसीयतकर्ता ने अपनी पत्नी के पक्ष में एक वसीयत बनाई, जिसमें अन्य बातों के अलावा, मेरी मृत्यु के बाद मेरी सभी संपत्तियों पर मेरी पत्नी का अधिकार होगा और वह खुद ही हर चीज की उत्तराधिकारी होंगी और मुथा अरुणाचल चेट्टी (भतीजा) और मेरी पत्नी को इसका अधिकार होना चाहिए। एक परिवार के रूप में सौहार्दपूर्ण ढंग से एक साथ रहें। यदि दोनों सहमत नहीं हो सकें और सौहार्दपूर्ण ढंग से एक साथ रह सकें, तो मेरी पत्नी 4,000 रुपये का भुगतान करेगी और उसे अलग कर देगी और फिर मेरी पत्नी शेष सभी संपत्तियों का पूर्ण अधिकारों के साथ आनंद उठाएगी। यदि वे दोनों जीवित रहेंगे - सौहार्दपूर्ण ढंग से, मुथा अरुणाचल चेट्टी स्वयं विधवा की मृत्यु के बाद बची संपत्तियों का आनंद लेंगे। वसीयत के निर्माण पर यह माना गया कि भतीजा, जो अपनी मृत्यु तक विधवा के साथ सौहार्दपूर्ण ढंग से रहता था, का वसीयतकर्ता की मृत्यु में निहित स्वार्थ था जिसे विधवा द्वारा किसी अजनबी के पक्ष में

वसीयतनामा स्वभाव द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता था। यह निर्णय केवल उस मामले का निर्णय करता है और इस जांच में बहुत प्रासंगिक नहीं है। उनके फैसले का भी हवाला दिया गया

एमएसटी में प्रिवी काउंसिल का आधिपत्य। भगवती देवी बनाम चौधरी भोलोनाथ ठाकुर()। यह एक उपहार इंटर विवो का मामला था। सुश्री को उपहार। चंदरबुट्टी, उनकी पत्नी, इन शब्दों में थीं -

शेष मिल्कीयट और मिनहाई संपत्ति, तैयार मोनो की मात्रा, सामान, दास और सभी घरेलू फर्नीचर के साथ, मैंने अपनी पत्नी सुश्री चंदरबुट्टी ठकुराइन के कब्जे में रख दिया है, ताकि वे अपने जीवनकाल के दौरान आनंद ले सकें। आदेश दें कि वह अपने जीवनकाल के दौरान मेरे, घोषणाकर्ता के पास मौजूद सभी संपत्तियों और दूधियों पर कब्जा कर सकती है, और सरकारी राजस्व का भुगतान करके, उससे प्राप्त लाभ को उचित कर सकती है, लेकिन वह किसी भी तरह से दूधिया सम्पदा को हस्तांतरित नहीं कर सकती है और दास; कि मेरी पूर्वोक्त पत्नी की मृत्यु के बाद दूध और घर का फर्नीचर मेरे कर्ता (दत्तक पुत्र) गिरधारी ठाकुर को हस्तांतरित हो जाएगा।

अधीनस्थ न्यायाधीश ने माना कि चंदरबुट्टी को उचित लाभ की शक्ति के साथ जीवन भर के लिए एक संपत्ति मिली और गिरधारी को उसकी मृत्यु पर निहित शेष राशि मिली। उच्च न्यायालय ने एक अलग

दृष्टिकोण अपनाया और माना कि चंद्रबुट्टी ने एक हिंदू विधवा के रूप में अपनी संपत्ति ले ली। इस पर प्रिवी काउंसिल की बैठक इस प्रकार होगी-

उनका आधिपत्य, चंद्रबुट्टी द्वारा ली गई संपत्ति की प्रकृति को बदलने के लिए भौतिक रूप से इसकी व्याख्या करने में, केवल इस अनुमान पर कि शायद क्या इरादा रहा होगा, उचित नहीं लगता है। यदि उसने केवल एक हिंदू विधवा की संपत्ति ली है, तो एक इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसका परिणाम यह होगा कि वह लाभ को अलग करने में असमर्थ होगी, या किसी भी स्थिति में, जो कुछ भी उसने उनसे खरीदा वह उसके पति की संपत्ति में वृद्धि होगी, और वादी को पुनर्प्राप्त करने का अधिकार होगा ऐसी सभी संपत्ति, वास्तविक और व्यक्तिगत, पर कब्ज़ा। लेकिन, दूसरी ओर, एक हिंदू विधवा के रूप में उसके पास कुछ अधिकार होंगे; उदाहरण के लिए, उसे कुछ परिस्थितियों में अधिकार होगा, यदि संपत्ति अंतिम संस्कार के लिए अपर्याप्त थी, जैसे- पेन्स या उसका रखरखाव, इसे पूरी तरह से अलग करने के लिए। उसके पास निश्चित रूप से अपनी संपत्ति बेचने की शक्ति होगी; और इसके बाद यह होगा कि गिरधारी के पास किसी निहित अवशेष के रूप में नहीं, बल्कि केवल एक आकस्मिक अवशेष के रूप में होगा। इससे यह भी होगा कि वह पूरी तरह से संपत्ति और कुछ परिस्थितियों में कानून का प्रतिनिधित्व करेगी और कुछ परिस्थितियों में सीमाओं का कानून संपत्ति के उत्तराधिकारियों के विरुद्ध चल सकती हैं, चाहे वे कोई भी हों।

उनके आधिपत्य को इस दस्तावेज़ में उन शब्दों को शामिल करने का कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखता है जो इन सभी परिणामों को अपने साथ ले जाएंगे, और वे इसके स्पष्ट अर्थ के अनुसार इसकी व्याख्या करने में अधीनस्थ न्यायाधीश से सहमत हैं। ये टिप्पणियाँ कुछ हद तक वर्तमान मामले से प्रासंगिक हैं लेकिन तथ्यों के आधार पर यह मामला अलग भी है। यह वसीयत वर्तमान मामले की वसीयत से भिन्न भाषा में लिखी गई थी। वहाँ एक स्पष्ट निषेध था, जिसमें विधवा को दूधिया सम्पदा और दासों का कोई भी हस्तांतरण करने से मना किया गया था। लल्लू बनाम जगमोहन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट के एक फैसले का भी संदर्भ दिया गया। वसीयत इस प्रकार थी-जब मैं मर जाऊँगा, तो मेरी पत्नी जिसका नाम सूरज है, उसकी मालिक होगी संपत्ति। और मेरी पत्नी के पास भी ऐसा करने की शक्तियाँ हैं जिस तरह से मेरे पास ऐसा करने की पूर्ण शक्तियाँ हैं जब मैं पूर्व-भेजा गया, और मेरी पत्नी की मृत्यु के मामले में, मेरी बेटी महालक्ष्मी उसके बाद उक्त संपत्ति की मालिक है। यह माना गया कि सूरज ने वसीयत के तहत केवल एक जीवन संपत्ति ली, उसकी मृत्यु के बाद शेष महालक्ष्मी को सौंप दी और वसीयत महालक्ष्मी को कर दी। वह अपने जीवित सूरज पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उसने एक निहित शेष ले लिया था जो उसकी मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारियों को चला गया।

पक्षों के प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार करने के बाद, हमारी राय है कि इस वसीयत के निर्माण पर नीचे की दो अदालतों की सर्वसम्मत राय को

परेशान करने के लिए कोई पर्याप्त आधार नहीं बनाया गया है। दोनों विद्वान वकीलों ने अंततः स्वीकार किया कि वसीयत में इस्तेमाल की गई भाषा वसीयतकर्ता के अंग्रेजी अर्थ में जीवन संपत्ति प्रदान करने के इरादे के साथ-साथ एक हिंदू विधवा की संपत्ति प्रदान करने के इरादे से सुसंगत थी। हालाँकि, श्री राजा अय्यर द्वारा यह आग्रह किया गया था कि सभी कानूनी आवश्यकताओं के प्रयोजनों के लिए विधवा को अलगाव की कोई व्यक्ति या निहित शक्ति प्रदान नहीं की गई थी, वह परिस्थिति

इस विचार को नकार दिया कि वसीयतकर्ता अपनी विधवा को हिंदू विधवा की संपत्ति प्रदान करने का इरादा रखता है, जैसा कि वह वडर को देती थी और निर्वसीयत के मामले में उसे मिलती थी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि बेटी को उपहार देने के शब्द उनके निर्माण का समर्थन करते हैं, जिसे वसीयत के शब्दों द्वारा आपके जीवनकाल तक विधवा की संपत्ति को सीमित करने और मलिक आदि जैसे शब्दों को हटाने से और भी बल मिला। विधवा की संपत्ति का वर्णन करते हुए, दूसरी ओर, श्री कृष्णास्वामी अयंगर ने तर्क दिया कि वसीयत में उनकी अलगाव की शक्तियों को सीमित करने और उन पर अंकुश लगाने वाले किसी भी शब्द की अनुपस्थिति, एक विपरीत इरादे का सुझाव देती है और बेटी की संपत्ति को इसमें शामिल होने के रूप में वर्णित किया गया है। विधवा की संपत्ति के पीछे होने के नाते और उसे विधवा के साथ एक साथ प्रदान नहीं किया गया था, और यह हिंदुओं की धारणा के अनुसार पूर्ण हिंदू विधवा की

संपत्ति का अर्थ था। हमारे निर्णय में, पहले से बताए गए कारणों से श्री राजा अय्यर के तर्क में बल है और परिणामस्वरूप, हम इस अपील को लागत सहित खारिज करते हैं।

अपील खारिज.

अपीलकर्ता के लिए एजेंट: एम. के. अयंगर

प्रतिवादी का एजेंट गणपत राय।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती मनीषा अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।